ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष रिपोर्ट

आयुष्मान की सरकार में एम्स आज खुद बीमार है

पंडित नेहरू की कई अनमोल सौगातों में 1956 में बना दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भारत के सबसे मशहूर चिकित्सा केन्द्रों में आज भी शायद पहले स्थान पर होगा। इस अस्पताल के डाक्टरों को गरीब जनता भगवान के आस पास का ही दर्जा देती है। बड़े से बड़े राजनेताओं तक का इलाज यहीं होता आया है। अत्याधुनिक चिकित्सीय व्यवस्थाओं और विश्व स्तरीय चिकित्सकों से सजा यह अस्पताल सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण आज खुद बीमार लगने लगा है।

बिहार, मधुबनी जिले के खोरसा गाँव से आये 65 वर्षीय रघुबीर पिछले 2 महीने से एम्स में अपनी आँखों का इलाज करा रहे हैं। रघुबीर ने बताया कि शुरूआती दिनों में तो उनको सिर्फ कार्ड बनवाने में ही दो हफ्ते लग गए। जानकारी न होने के कारण रोज लाइन में लगते और जब तक नंबर आता तब तक या तो खिड़की बंद हो जाती थी या फिर कई दफा तो गलत लाइन में लग जाते थे। बड़ी दिक्कतों से आज उनका चश्मा बन सका है।

हालाँकि, यहाँ मरीजों का पंजीकरण 8.30 पर सुबह प्रारंभ होता है पर 100-100 मीटर लम्बी कतारें हर विभाग के सामने कार्ड बनवाने के लिए रात 3 बजे से ही लग जाती हैं। हर विभाग का एक तय नंबर तक ही पंजीकरण होता है, उसके बाद जो लोग कतार में हैं उन्हें अगले दिन या महीनों तक आना पड़ सकता है जब तक कार्ड न बन जाए।

50 वर्षीय गेंदालाल उत्तर प्रदेश के एटा जिले से आये हैं। गेंदालाल अपनी पत्नी को कैंसर की बीमारी के चलते खो चुके हैं पर वही समस्या बेटे के साथ होने पर अब एम्स का रुख किया। यहाँ पहुँच कर देखा तो पूरी एक दुनिया ही कैंसर से पीड़ित है और इस भीड़ में सिर्फ पंजीकरण कार्ड बनवा पाना ही एक लड़ाई जीतने सा है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगने पर 2 बजे दोपहर में डाक्टर से मिल कर सिर्फ ये पता चला कि रेडीओलोजी की मशीन काम नहीं कर रही और उन्हें सफदरजंग रेफेर कर दिया गया। सफदरजंग में भी यही बात बोल कर वापस एम्स रेफेर कर दिया।

अब वो नहीं जानते कि क्या करें? इसलिए गेंदालाल ने फैसला किया है कि अपनी एकमात्र दो बीघा पुश्तैनी जमीन बेच कर बेटे का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में कराएंगे।

एम्स के ही एक मेडिकल स्टोर सुपरवाइजर ने बताया कि ।5 प्रतिशत कैंसर पीड़ितों की मृत्यु सिर्फ उपचार में देरी के कारण ही हो जाती है। इस देरी के मुख्य कारणों में बेड की अनुपलब्धता और रेडीओलोजी मशीन का आगे कई महीनों तक बुक रहना शामिल है।

डॉक्टर जीजू रहने वाले कश्मीर के हैं और अपनी खुली विचारधारा के कारण वहाँ के कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर भी। इसलिए, 45 की उम्र में अब सिक्किम में जा बसे। पांच रोज पहले उनके बड़े भाई का सड़क हादसे में एक्सीडेंट हुआ जिनका इलाज एम्स ट्रामा सेंटर में चल रहा है। फिलहाल भाई कोमा में है। भाई के इलाज के लिए उसके अकाउंट से पैसे निकालने होंगे। इसके लिए बैंक को अस्पताल प्रशासन के सत्यापन की आवश्यकता है। जीजू रोज ट्रामा सेंटर में एमएस ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं पर अस्पताल प्रशासन सत्यापित करने के लिए ऐसे आना-कानी कर रहा है जैसे एम्स के फण्ड से देना पड़ रहा हो।

भुगतना पड़ता है बीके के मरीजों को भी

फ़रीदाबाद के बीके अस्पताल के आपातकाल में आने वाले ज्यादातर मरीजों को दिल्ली के सफदरजंग या एम्स रेफर किया जाता है। क्योंकि बीके अस्पताल में ओटी की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है। एम्स के आज के हालातों में कितने लोगों को उचित इलाज मिल सकेगा? पैसे के दम पर सत्ता में बैठे निकम्मे राजनेताओं को अगर ये समझ होती कि लोग एम्स इसलिए आते हैं क्योंकि राज्यों में चिकित्सा सुविधा पर भरोसा जानलेवा है, तो ये आज एम्स में कतारों को भी जानलेवा न बना देते। मोदी के राज में आज एम्स खुद बीमार है और उनकी सरकार का 'आयुष्मान भारत' भी इसी गति को प्राप्त होगा।

रमेश चंद मिश्र दो वर्ष पहले सोशल वेलफेयर विभाग एवं शोभा राय जिनके पति श्रीराम राय 8 वर्ष पहले कैंसर अस्पताल से सेवानिवृत हुए एम्स के ईएचएस स्टाफ हैं। दोनों का सम्मिलित रूप से मानना है कि एम्स अब वैसा नहीं रहा जिसके लिए इसे जाना जाता था।

यहाँ बैक ऑफिस का जो काम पहले एम्स के ही कार्मिक किया करते थे अब व प्राइवेट कम्पनी टीसीएस के हाथ में मोदी सरकार ने दे दिया है। कंपनी के लोग पुराने एम्स कर्मियों को न पहचानते हैं न बाइज्जत बात ही करते हैं। अपने ही संस्थान, जिसको जीवन के इतने वर्ष दिए, उसमे ऐसा सौतेला व्यवहार और इलाज के लिए धक्के खाना बहुत खलता है।

एम्स की सुरक्षा में लगे गार्ड वहाँ आये लोगों के प्रति ऐसा बर्ताव करते मिले जैसे वे मरीज नहीं कोई जानवर हों। ज्यादातर मरीजों और उनके साथ आये परिजनों का कहना था कि एक तो कोई मार्गदर्शन के लिए नहीं है इतने बड़े संस्थान में, ऊपर से ये गार्ड इतनी बेइज्जती से बात करते हैं कि खून के घूँट पी कर ही रह जाना पड़ता है, क्योंकि इलाज कराना मजबूरी है।

कुछ मरीजों ने सुरक्षाकर्मियों पर धांधली का भी आरोप लगाया। नाम न बताने की शर्त पर एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के एक कर्मचारी ने इन आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा कि एम्स में ज्यादातर भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है। इसी क्रम में सिक्यूरिटी का भी जिम्मा एसआइएस और ग्रुप 4 जैसी कंपनी के हवाले है। चूँकि इन सुरक्षाकर्मियों की जान पहचान स्टाफ से हो चुकी है इसलिए ये लोगों से 1000 से 5000 रूपए तक ले कर उनका कार्ड बनवाना और ज्यादा पैसे देने की सूरत में टेस्ट इत्यादि करवाने का धंधा करते देखे जाते हैं। शंका तो यह भी है कि खुद प्रशासन के लोग भी इस रैकेट में शामिल हैं।

एम्स में आने वाली भीड़ के अनुपात में डाक्टरों की संख्या लगभग नगण्य है। डब्लूएचओ के मापदंडों से 1000 मरीजों पर एक चिकित्सक का होना अनिवार्य है परंतु भारत में 10000 लोगों पर एक डाक्टर उपलब्ध है। इस अनुपात को एम्स के सन्दर्भ में देखा जाये तो अन्तर बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत में एम्स सरीखे अस्पताल कम ही हैं। मोदी ने योगी के गोरखपुर में भी नया एम्स बनाने की घोषणा तो कर दी पर पहले जो एम्स बने हुए हैं उनके हाल दिन प्रतिदिन खस्ता ही होते जा रहे हैं। इसकी सुध लेने का वक्त मोदी या योगी ब्रिगेड के पास नहीं है।

भाजपा सरकार के आने के बाद से एम्स का अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। इससे ज्यादातर गरीब जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, इसकी चिकित्सा सुविधाओं से बाहर हो गए। लाइन में लग कर अपॉइंटमेंट लेना नाकों चने चबाना है। इस बीच मोदी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री का शर्मनाक वक्तव्य आया कि बिहार से आने वाले लोगों को एम्स से भगा दिया जाए क्योंकि ये छोटी छोटी बिमारियों के लिए भी आ जाते हैं। बिना जांचे कोई बीमारी बड़ी छोटी कैसे है ये मंत्री जी ही बता सकते हैं।

'आयुष्मान भारत' जैसी प्रचार योजनाओं के तहत 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने के नाम पर बीमा कंपनियों की जेब भरने वाली मोदी टीम को इस शानदार अस्पताल को बर्बाद करने का हुनर खूब पता है। एम्स की ही 45 वर्षीय महिला कर्मचारी की सुनें तो जिनको ये भ्रम है कि निजी हाथों में जा कर सब ठीक हो जाता है वो एम्स को आ कर देख लें, जो अभी आंशिक रूप से ही निजी हाथों में है पर इसकी बर्बादी पूर्ण रूप से झलकने लगी है।

दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक अंध विश्वासी "पेड न्यूज" छपा है !

इसे आम जनमानस अखबार की खबर ही समझेगा! इसके अनुसार विश्व के साइंटिस्ट साइंस की स्टडी छोड़कर मंत्र पढना शुरू कर देगें क्योंकि ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने उनको मंत्र के बारे में बता दिया! जब संसार के इतने शक्तिशाली राष्ट्र ये सब मानने को मजबूर हो गए तो हम विश्व गुरू हो गए या नही? हम सबको इनको मानना चाहिए!

एक एम बी बी एस डाक्टर का भी बयान है कि वे असाध्य एलर्जी से ग्रस्त थे तो गुरू जी की अभिमंत्रित रोटी खाने के बाद केवल दस दिन में ही वो रोग गायब हो गया! जब एम बी बी एस डाक्टर का ये हाल है तो आम आदमी इन तथाकथित "गुरूओ" का थूका हुआ क्यों नही चाटेगा और ये लोगों को इसी तरफ प्रेरित करने के लिए है! क्या उस एम बी बी एस डाक्टर की डिग्री वापिस लेकर इसे घर नही बैठा देना चाहिए और जिसने भी इसको डिग्री दी है उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए!

ये फोटो व खबर लगा रखी है कि अमेरिका के सीनेटर लाइन लगाकर गुरू जी से मिले! इनको ये नही पता कि अमेरिका साइंटिफिक सोच पर चलता है! वे अतिथि देवो भव की भावना का सही में पालन करते हैं और आप लोग इस बात को दूसरे तरीके से महिमामंडित कर रहे हो! क्या ये पाखंड फैलाना नही है और ये काम सरेआम हो रहा है और क्योंकि हमारे देश में विदेशों के पीछे चलने की आदत है तो इन देशों का नाम लेकर पाखंड की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है! सरेआम ये कहा जा रहा है कि साइंस कुछ नही है और मंत्र ही सबकुछ हैं! ये सब होने के बाद भी हम इस देश को आगे बढने की उम्मीद में हैं! ये जितने भी डाक्टर "मेरिटधारी" हैं वे सब इस पाखंड का शिकार हैं तो उनकी मैरिट का फायदा ही क्या जब उन्हें साइंस के आधार पर चलना ही नही तो! इस बात पर मनन कीजिए कि साइंस बड़ी या पाखंड!

-साइबर नजर

कोटा: गौशाला में 3 दिन में मरी 27 गायें

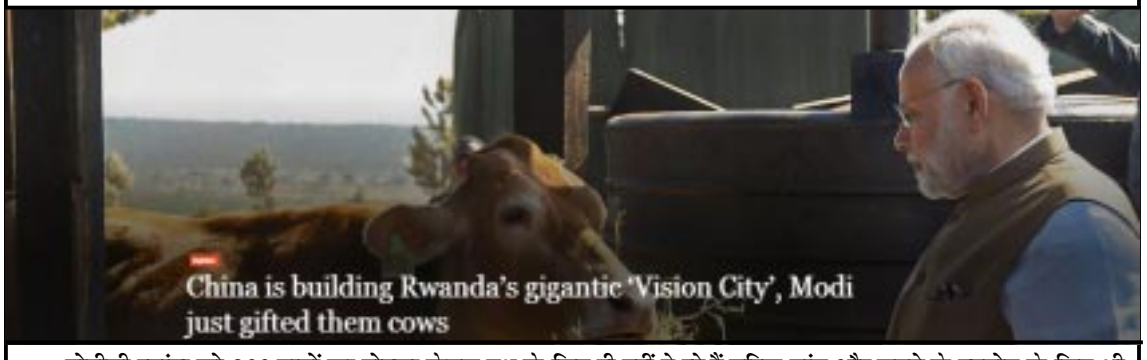

मोदीजी रवांडा को 200 गायों का तोहफा केवल दूध के लिए ही नहीं दे रहे हैं बल्कि मांस और चमड़े के उपयोग के लिए भी दे रहे हैं। तथाकथित गो रक्षकों और गोपुत्रों को भी यह बात समझ में आनी चाहिए। वैसे भारत में भी गोहत्या पर सारे देश में प्रतिबन्ध नहीं है, कुछ राज्यों को छूट भी दी गई है। यूनिफार्म सिविल कोड की बात करने वाली भाजपा अपने ही देश में अलग अलग कोड अपना रही है।

एक तरफ भाजपा गायों की रक्षा के नाम पर पूरे देश में उन्माद पैदा कर रही हैं, वहीं उसके शासन वाले राजस्थान में गौशालाओं में गायों की बुरी हालत है। कोटा में धर्मपुरा गौशाला में बारिश के कारण ही 3 दिन में 27 गायों की मौत हो चुकी है और दो दर्जन से ज्यादा गायें मरने की हालत में पड़ी हुई हैं। गौशाला में गायों को इस तरह से ठूंस-ठूंसकर भरा गया है कि वे हिल-डुल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हीं के बीच पड़ी मरी हुई गायों की लाशें सड़ रही हैं, और बदबू मार रही हैं। जीवित बची गायों में संक्रमण का खतरा भी फैल रहा है।

पत्रिका की खबर के अनुसार, गौशाला में इस वक्त भी दो दर्जन से ज्यादा गायें और बछड़े मरणासन्न अवस्था में तड़प रहे हैं और उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर तो दूर साधारण कर्मचारी भी नहीं हैं। गौशाला के कर्मचारी बता रहे हैं पहले भी हर दिन तीन-चार गायें मरती थीं, लेकिन अब बारिश के कारण हर दिन 10-12 गायें मरने लगी हैं। नगर निगम ने निगरानी के लिए कर्मचारी लगा रखा है, लेकिन वह कभी समय पर नहीं पहुंचता। कहने को गौशाला में पशु चिकित्सक भी लगा रखा है, लेकिन गायें लगातार मरती जा रही हैं।

गायों का मुद्दा भाजपा केवल धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बाकी सारे प्रदेश में गायों और अन्य जानवरों की बुरी हालत है। उदयपुर की गिरवा तहसील के डेडकिया गांव में तो बिजली का तार एक मकान पर गिरने से 7 जानवर करंट के कारण तड़प-तड़पकर मर गए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वैसे तो गायों की परवाह नहीं करते, लेकिन करंट से गायों के मरने के बाद राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसके कार्यकर्ता डेडकिया में सक्रिय हो गए और लोगों को भड़काने में लगे हैं।

मोदी नरम : किसानों के नाम पर 5400 करोड़ हज़म

मुकेश असीम (म. मो.) महाराष्ट्र के परभणी जिले के गंगाखेड़ चीनी मिल के प्रोमोटर रत्नाकर गुट्टे ने हजारों किसानों के नाम पर बैंकों से 5400 करोड़ का कर्ज लिया, फिर इसे अपनी 22 शेल कंपनियों के जरिये हजम कर लिया।

मोदी जी कहते हैं उन्होने 2 लाख शेल कंपनी बंद कराईं पर उनमें ये गबन करने वाली शेल कंपनी शामिल नहीं थीं, उनमें तो वही थीं जिनसे गबन करके काम निपटाया जा चुका था और अब उन्हें बंद कर सबूत मिटाने थे, वो काम भी मोदी जी की कृपा से सम्पन्न हुआ।

ये कर्ज बीजेपी सरकार आने के बाद 2015 के बाद से लिए गए; यह गबन जाहिर तब हुआ जब किसानों को बैंकों से कर्ज वसूली के नोटिस मिलने शुरू हुए। पर 5 जुलाई को पुलिस रिपोर्ट होने के बाद भी अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अब यह 5400 करोड़ बट्टे खाते में जाएगा और मेहनतकश जनता का पेट काटकर सरकार बैंकों को इसकी भरपाई के लिए पूंजी की एक और किश्त जारी करेगी।

पर मोदी सरकार में यह घोटाला नहीं है!

अलवर में नरोदा पाटिया

नरोदा पाटिया से
कम आतंकित नहीं है अलवर
जहाँ एक मुसलमान को गौ पालना नहीं फली

नरोदा पाटिया ने
मोहनजोदड़ो-हड़प्पा का कर्ज उतारा
अलवर में हिंदुत्व की लुप्त भागीरथी बह चली

नरोदा पाटिया में
क़त्ल-लूट-बलात्कार का अंधड़ रहा
अलवर में संघियों की नागपुरी शाखा है पली

नरोदा पाटिया में
संविधान और मीडिया छिपे थे शर्मसार
अलवर में कानून की किताब पुलिस थाने में जली

- विकास नारायण राय